साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Global School Of Excellence, Obedullaganj

वर्ष : 9, अंक : 47 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 10 जुलाई 2024 से 16 जुलाई 2024 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

पर्यावरण अनुकूलता एवं पर्यावरण संबंधी चुनौतियों का समाधान कारक होगा

पौध-रोपण का महाअभियान - लोकसभा अध्यक्ष श्री बिरला

लोकसभा अध्यक्ष ने स्कूली बच्चों के साथ इंदौर के बिजासन के अटल वन में किया पौध-रोपण

भोपाल (एजेंसी)लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने मंगलवार को एक पेड़ माँ के नाम अभियान में इंदौर में चल रहे 51 लाख पौधे लगाने के महा अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने इंदौर के बिजासन के समीप अटल वन में पौध-रोपण भी किया। श्री बिरला ने पौध-रोपण अभियान को समय की सबसे बड़ी जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि जब पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के दुषपरिणामों का सामना कर रहा है ऐसे में यह अभियान पर्यावरण अनुकूलता की दिशा में देश और दुनिया को नया दृष्टिकोण देते हुए नई राह दिखायेगा।

लोकसभा अध्यक्ष श्री बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया है। इस अभियान को मध्यप्रदेश विशेषकर इंदौर में तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। यह अभियान जन-आंदोलन का रूप ले चुका है। उन्होंने कहा कि पौध-रोपण हमारी संस्कृति, संस्कार एवं अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। यह अभियान वर्तमान के साथ भविष्य को भी सुखद बनाने का अभियान है। देश एवं विश्व की पर्यावरण संबंधी चुनौतियों के समाधान का माध्यम भी बनेगा। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने कहा कि यह अभियान मानव जीवन को बचाने का वृहद अभियान है। यह एक अच्छा कार्य है। इस अभियान को निरन्तर आगे बढ़ाते रहना चाहिए। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वृक्ष धरती का श्रृगांर है। यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। वृक्ष से ही जीवन की निर्भरता है। वृक्ष हमें जीवन बचाने के लिए सब कुछ देता है। हमारा फर्ज बनता है कि अधिक से अधिक पौधे लगाये और उनकी सुरक्षा का संकल्प लें। इंदौरमहापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव ने स्वागत भाषण देते हुए इंदौर में चलाए जा रहे पौध-रोपण अभियान की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह अभियान समाज के हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी से जन आंदोलन बन चुका है। राज्य सरकार ने जहां एक ओर साढ़े 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इसमें से इंदौर शहर में ही 51 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री नागर सिंह चौहान, पशुपालन मंत्री श्री लाखन पटेल, सांसद श्री शंकर लालवानी , उत्तरप्रदेश विधान परिषद के सदस्य श्री महेन्द्रसिंह, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष श्री सावन सोनकर, ?विधायक श्री महेन्द्र हार्डिया, श्री रमेश मेंदोला, श्री मधु वर्मा सहित जन-प्रतिनिधि मौजूद थे। कार्यक्रम में सभी अतिथियों ने हजारों स्कूली बच्चों के साथ बिजासन के सामने स्थित अटल वन में पौध-रोपण किया। इस अवसर पर श्री ओम बिरला ने पौध-रोपण के ब्रांड एम्बेसेडर श्री विष्णु लांबा और कुमारी प्रसिद्धि का सम्मान भी किया।

लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने पितृ पर्वत में पूजन-अर्चन कर किया वृक्षारोपण

इंदौर लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला आज इंदौर पहुँचे। श्री ओम बिरला पितृ पर्वत पहुँचे। यहाँ उन्होंने श्री हनुमान जी की प्रतिमा के दर्शन किये। उन्होंने पूजन-अर्चन कर वृक्षारोपण किया। नगरीय विकास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय एवं वन मंत्री श्री नागर सिंह चौहान, विधायक श्री रमेश मेंदोला सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इंदौर पहुंचने पर श्री बिरला का मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद श्री शंकर लालवानी और महापौर इंदौर श्री पुष्यमित्र भार्गव द्वारा स्वागत किया गया। रेसीडेंसी कोठी इंदौर में संभागायुक्त श्री दीपक सिंह, पुलिस कमिश्नर श्री राकेश गुप्ता, कलेक्टर श्री आशीष सिंह एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने भी लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला से सौजन्य भेंट की। लोकसभा अध्यक्ष श्री बिरला को गार्ड ऑफ़ ऑनर भी दिया गया।

हर व्यक्ति पौधा लगाए और पेड़ बनने तक करें देखभाल - महिला बाल विकास मंत्री सुश्री भूरिया

भोपाल महिला बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने भोपाल के जवाहर बाल भवन में एक पेड़ माँ के नाम अभियान में अशोक का पौधा लगाया। इस अवसर पर आयुक्त महिला बाल विकास श्रीमती सूफिया फारूकी वली ने भी अमरूद का पौधा लगाया।

मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में पौध-रोपण किया जा रहा है। उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत हर व्यक्ति एक पौधा लगाए और उस पौधे की देखभाल तब तक करें जब तक वह पेड़ नहीं बन जाता। सुश्री भूरिया ने कहा कि इस क्रम में प्रदेश के सभी ऑगनवाड़ियों केन्द्रों में भी पौध-रोपण किया जायेगा। उन्होंने बाल भवन में बच्चों द्वारा बनाई गई चित्रों, संगीत कक्ष, लाइब्रेरी आदि का भ्रमण कर जानकारी ली। इस अवसर पर जवाहर बाल भवन की संचालक श्रीमती शुभा वर्मा सहित सभी अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहें।

सुरक्षित भविष्य के लिए पौध-रोपण जरूरी - राज्यपाल श्री पटेल

राज्यपाल ने एक पेड़ माँ के नाम'' अभियान में किया पौध-रोपण

भोपाल

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि सुरक्षित भविष्य के लिए पौध-रोपण ज़रूरी है। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान में पौधे ज़रूर लगाए। राज्यपाल श्री पटेल ने स्वयं अभियान के तहत राजभवन परिसर में अधिकारी-कर्मचारियों के साथ पौध-रोपण किया। उन्होंने क्रिसमस ट्री का पौधा रोपा। राज्यपाल के प्रमुख सचिव श्री मुकेश चंद गुप्ता, अपर सचिव श्री उमाशंकर भार्गव, विधि अधिकारी श्री उमेश श्रीवास्तव और राजभवन के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

अभ्यारण तीन जिलों के वन क्षेत्र को मिलाकर बनाया जाएगा।

भोपाल करीब चार दशक के इंतजार के बाद ओंकारेश्वर अभ्यारण्य बनने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। इसकी वजह है इससे संबंधित फाइल अब तेजी से दौड़ना शुरू हो गई है। यह अभ्यारण तीन जिलों के वन क्षेत्र को मिलाकर बनाया जाएगा। इसमें खंडवा, देवास और हरदा जिले शामिल हैं। इसका क्षेत्रफल करीब 614 वर्ग किलोमीटर संभावित है। फिलहाल इसका मामला शासन स्तर पर लंबित चल रहा था । इसके पीछे सरकार की मंशा इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध की वजह से वन क्षेत्र डूबने से वन्य प्राणियों को सुरक्षित आवास व संरक्षण देना है। अब जिस तरह से फाइल दौड़ रही है उससे माना जा रहा है कि अगले माह तक इस नए अभ्यारण्य की अधिसूचना जारी हो सकती है।

इस अभ्यारण्य के बनने से बाघ, तेंदुआ, सियार, चीतल, भालू जैसे वन्य प्राणियों को बेहतर आवास सुविधा तो मिलेगी ही साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। दरअसल, इन दिनों इंदिरा सागर के बैकवाटर में उभरे 50 से अधिक टापुओं से घिरे अभ्यारण्य के लिए प्रशासन सभी पक्षों से चर्चा व सुझाव लेने की कवायद में जुटा हुआ है। इस मामले में हाल ही में जनप्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में भी अभ्यारण्य को लेकर सहमति बन चुकी है। बैठक में सांसद ज्ञानेश्वर पाटील , पंधाना और मांधाता विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, कलेक्टर, सीसीएफ, डीएफओ आदि मौजूद थे। इस दौरान डीएफओ राकेश कुमार डामोर ने अभ्यारण्य की कार्ययोजना और प्रगति से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि जल्द ही ग्राम सभाओं में इस प्रस्ताव की जानकारी ग्रामीणों को देकर उनकी सभी की आपत्ति और सुझाव लेकर एक प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाएगा। ओंकारेश्वर अभ्यारण्य के लिए खंडवा जिले का 450 वर्ग किमी, देवास 225 वर्ग किमी तथा कुछ हिस्सा हरदा जिले के वन क्षेत्र का आ रहा है। अभ्यारण्य की जद में कोई भी राजस्व गांव नहीं आ रहा है। भौगोलिक और प्राकृतिक रूप से यह वन क्षेत्र बाघों के लिए सुरक्षित पनाहगाह भी साबित होगा। यहां एक ओर इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध का बैक वाटर फैला है, दूसरी ओर सतपुड़ा की ऊंची-ऊंची पहाडियां पूरे क्षेत्र को सुरक्षित बनाती हैं।

देरी की यह वजह अभ्यारण्य का कार्य करीब 39 साल से चल रहा है। एनवीडीए द्वारा आवश्यक अधोसंरचना विकास पर करोड़ों रुपये खर्च किए है। समय-समय पर आपत्तियां और केंद्र सरकार के मापदंड़ों की वजह से अधिसूचना टलती रही। पांच साल पहले अभ्यारण्य को हरी झंडी मिलना लगभग तय हो गया था, लेकिन कालीसिंध लिंक परियोजना की वजह से अधिसूचना टल गई है। बताया जाता है कि इस परियोजना की पाइप लाइन बिछाने का कार्य अभ्यारण्य के अंदर से होना था, इसलिए राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से मामला अटक गया था।

संरक्षण का प्रस्ताव देश और प्रदेश की प्रगति के उद्देश्य से बांध बनाकर हजारों हेक्टेयर जंगल को डुबाने वाले शासन-प्रशासन को वन्य जीवों की कितनी चिंता है, यह ओंकारेश्वर अभ्यारण्य की सुस्त रफ्तार से स्वत- ही स्पष्ट है, जबकि इस अभ्यारण्य को वन्य प्राणियों को संरक्षण देने के लिए प्रस्तावित किया गया था। नर्मदा नदी पर बने इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर सागर बांध के कारण खंडवा देवास और हरदा जिले का 40332 हेक्टेयर सघन वन क्षेत्र प्रभावित हुआ था। इसमें बेशकीमती पेड़ों के अलावा कई प्रकार के शाकाहारी और मांसाहारी प्राणी थे। बांध बनने के बाद इन वन्य प्राणियों को संरक्षित करने के लिए ओंकारेश्वर अभ्यारण्य प्रस्तावित था। इसकी जिम्मेदारी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए) को दी गई थी। दिसंबर 1987 में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की निगरानी में कमेटी गठित की थी। सेंचुरी बनाने के लिए आवश्यक तैयारी और प्लान के अनुरूप निर्देश तय किए गए थे। इसके चलते अभ्यारण्य क्षेत्र में अधोसंरचनात्मक विकास के कार्य हुए। इनमें संचालन कार्यालय भवन, वनपाल, वनरक्षक आवास के अलावा सात वाच टावर बन चुके हैं।

यह वन्य जीव है इलाके में

इस वन क्षेत्र में टाइगर, तेंदुआ, लकड़बग्घा, भालू सियार जैसे अनेक शाकाहारी, मांसाहारी और विभिन्न प्रजाति के पक्षी निवास करते हैं। ओंकारेश्वर अभ्यारण्य का नोटिफिकेशन होने के साथ ही यहां दो अभ्यारण्य के बीच एक कॉरिडोर बन जाएगा। दरअसल, देवास जिले की नेशनल सेंचुरी सीधे ओंकारेश्वर सेंचुरी से जुड़ेगी और इनके बीच कॉरिडोर बनेगा. ।खिवनी में टाइगर भी हैं। इससे भालू, तेंदुआ, हिरण सहित अन्य वन्य प्राणियों का मूवमेंट बढ़ेगा।

जन और जनजातीय संस्कृति के विकास में अव्वल मध्यप्रदेश

जनजातीय विरासत के लिये लगभग 41 हजार करोड़ रूपये का बजट आवंटित

इंदौर (नगर प्रतिनिधि) **जनजातीय वर्ग के समग्र विकास के लिये राज्य सरकार बेहद संवेदनशील है। इस वर्ग के लिये सरकार की संवेदनशीलता इसी तथ्य से परिलक्षित होती है कि सालाना बजट 2024-25 में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति (उप योजना) के लिये 40 हजार 804 करोड़ रूपये बजट आवंटित किया गया है। यह बजट वर्ष 2023-24 से 3 हजार 856 करोड़ रूपये (करीब 23.4 प्रतिशत) अधिक है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की जनजातीय वर्ग के कल्याण और इन्हें समर्थ बनाने की संवेदनशील पहल पर ही इस वर्ष जनजातीय कार्य विभाग को पहले से अधिक धनराशि आवंटित की गई है। जनजातीय बंधुओं और इनकी समृद्ध संस्कृति के संरक्षण और विकास के लिये सरकार द्वारा अनेक नवाचारी कदम उठाये जा रहे हैं। सरकार के प्रयासों से जनजातीय वर्ग के विद्यार्थी, युवा, खिलाड़ी और कलाकार अब विकास की एक नई राह पर चल पड़े हैं।**

जनजातीय वर्ग के बच्चों की शिक्षा-दीक्षा की ठोस चिंता करते हुए सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में सीएम राइज स्कूलों के निर्माण के लिये 667 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान नियत किया है। इस वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के प्रति प्रोत्साहित करने के लिये सरकार ने 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालयीन का छात्रवृत्ति के लिये 500 करोड़ रूपये प्रावधान किया हैं। सरकार की अत्यंत सराहनीय पहल आकांक्षा योजना में जनजातीय वर्ग के 10वीं पास विद्यार्थियों को मध्यप्रदेश सरकार नीट, क्लैट एवं जेईई की निःशुल्क कोचिंग देने का कार्य कर रही है। निःशुल्क कोचिंग के साथ-साथ सरकार जनजातीय विद्यार्थियों को टैबलेट भी देगी। साथ ही डेटा प्लान भी सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के लिये सरकार ने बजट में 10 करोड़ 42 लाख रूपये आरक्षित कर दिये हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जन-मन) के तहत विशिष्टतः असुरक्षित जनजातीय समूहों (पीव्हीटीजी) के सर्वांगीण विकास के लिये मध्यप्रदेश सरकार प्रतिबद्धता पूर्वक प्रयास कर रही है। मध्यप्रदेश में तीन विशेष पिछड़ी जनजातियां बैगा, भारिया एवं सहरिया निवास करती हैं। पीएम जन-मन योजना के तहत इन विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में बहुउद्देश्यीय केन्द्र, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़क, समग्र शिक्षा एवं विद्युतीकरण कार्य कराये जायेंगे। सरकार ने जारी वित्त वर्ष के बजट में इन कामों के लिये 1 हजार 607 करोड़ रूपये प्रावधानित किये हैं। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों (पीव्हीटीजी) आहार अनुदान योजना के तहत इन जनजाति समूह बाहुल्य ग्रामों में जनजातीय परिवारों को 1 हजार 500 रूपये प्रति माह आहार अनुदान के रूप में सहायता राशि दी जाती है। इसके लिये सरकार ने बजट 2024-25 में 450 करोड़ रूपये आवंटित किये हैं। इस राशि से बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजातीय परिवारों को निःशुल्क आहार अनुदान वितरित किया जाएगा। विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र विकास के लिये सरकार 2024-25 में 100 करोड़ रूपये अतिरिक्त व्यय करेगी। वहीं इसी योजना के अंतर्गत विशेष जनजातीय क्षेत्रों में 217 नये आंगनवाड़ी भवनों का भी निर्माण किया जा रहा है। इन नये आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिये बजट 2024-25 में 150 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत का विस्तार अर्थात पेसा एक्ट में पेसा नियम, नवम्बर, 2022 से मध्यप्रदेश में लागू है। यह नियम, प्रदेश की कुल 5 हजार 210 ग्राम पंचायतों तथा 11 हजार 783 गावों में प्रभावशील है। सरकार के प्रयासों से इन नियमों के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग जनजातीय वर्ग के हितों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये अत्यंत प्रभावशाली साबित हो रहा है। इस पेसा एक्ट से जनजातीय वर्ग अपने क्षेत्र, अपनी परम्पराओं, अपनी संस्कृति और अपनी जरूरतों के मुताबिक फैसले लेकर विकास की राह में आगे बढ़ सकेंगे।

मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड ने 'एमपी टूरिज्म मास्टरक्लास' का किया आयोजन

भोपाल मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड ने मध्यप्रदेश भवन में 'एमपी टूरिज्म मास्टरक्लास' कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स और होटल व्यवसायियों का प्रशिक्षण तथा प्रदेश में पर्यटन उत्पादों और गंतव्यों का प्रदर्शन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य मध्य प्रदेश को %ऑफबीट मल्टीस्पेशलिटी डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना।

कार्यशाला का उद्घाटन मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड की अतिरिक्त प्रबंध संचालक सुश्री बिदिशा मुखर्जी और उपसंचालक श्री विवेक जूड तथा मप्र पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के मुख्य महाप्रबंधक श्री अमन मिश्रा तथा टूर ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष श्री राजीव मेहरा ने दीप प्रज्जवलित कर किया। कार्यशाला में सुश्री मुखर्जी ने बताया कि 785 बाघों के साथ प्रसिद्ध टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया और चीता स्टेट ऑफ इंडिया% ने 2023 में पर्यटकों की संख्या में एक नया पर्यटन रिकॉर्ड स्थापित किया है, जो 2022 में 34.1 मिलियन की तुलना में 112.1 मिलियन है। उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला के माध्यम से हितधारकों के बीच मध्यप्रदेश की पर्यटन क्षमता की समझ को गहरा करने का प्रयास किया गया है। मध्यप्रदेश के पर्यटन उत्पादों जैसे वन्यजीव पर्यटन, विरासत पर्यटन, आध्यात्मिक पर्यटन, इंट्रास्टेट एयर टैक्सी सेवा, चंदेरी क्राफ्ट हैंडलूम गांव प्राणपुर आदि के बारे में जानकारी दी गई।

पौधरोपण को जन आंदोलन बनाये - कलेक्टर श्री अस्थाना ''एक पौधा माँ के नाम'' अभियान के तहत कलेक्टर ने पंचायत उरहेरा में किया वृक्षारोपण

मुरैना /पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य ''एक पौधा मां के नाम'' अभियान के तहत कलेक्टर श्री अंकित अस्थाना और जिला सीईओ डॉ. इच्छित गढ़पाले ने जौरा जनपद की ग्राम पंचायत उरहेरा के पंचायत भवन पर करंच का पेड़ लगाया। पौधरोपण के दौरान कलेक्टर श्री अंकित अस्थाना ने कहा कि पौधरोपण को जन आंदोलन बनाएं और इसमें सभी अपनी-अपनी सहभागिता निभाए। ग्लोबल वॉर्मिंग व गर्मी से निजात दिलाने में पेड़ों से प्राण वायु मिलती है। कलेक्टर ने कहा कि हम सबकी जिम्मेदारी भी है कि वह पौधे लगाए तथा उनकी सुरक्षा भी करें, क्योंकि यह हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही जरूरी है। पौधरोपण के बाद जब पौधे विशाल वृक्ष का रूप लेते है तो उनसे हमें फल एवं छाया प्राप्त होती है। अब पेड़ हमें सांस लेने के माध्यम बन गए हैं, क्योंकि ग्लोबल वॉर्मिंग व गर्मी बढ़ गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हितग्राहियों के खाते में साढ़े तीन हजार करोड़ रूपये की राशि की अंतरित

भोपाल (एजेंसी) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर रिफिल के लिए 24 लाख महिलाओं के खाते में 41 करोड़ की राशि पहुंचीमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज टीकमगढ़ जिले के छिपरी ग्राम की विशाल जनसभा में मध्यप्रदेश में चल रही चार बड़ी योजनाओं में 2.89 करोड़ हितग्राहियों के बैंक खातों में 3575 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण सिंगल क्लिक से किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के मध्यप्रदेश के 2.89 करोड़ हितग्राहियों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक से 3575 करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण किया। मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहना योजना में 1.29 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में 1574 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान उनके बैंक खातों में सिंगल क्लिक से किया। डॉ. यादव ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में प्रदेश के 81 लाख से अधिक किसानों को वर्ष 2024-25 की प्रथम किश्त और योजना की 9वीं किश्त की राशि 1630 करोड़ रुपए का भुगतान हितग्राहियों के बैंक खाते में सिंगल क्लिक से किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 24 लाख महिलाओं को गैस सिलेंडर रिफिल के लिए 41 करोड़ से अधिक राशि तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले 55 लाख हितग्राहियों के बैंक खाते में 330 करोड़ से अधिक राशि भी अंतरित की। गैस सिलेंडर रिफिल योजना में 450 रूपये प्रति हितग्राही का भुगतान किया गया।

मुख्यमंत्री ने जतारा के विधायक श्री हरिशंकर खटीक की मांग पर छिपरी ग्राम का नाम बदलकर मातृ धाम करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि मातृ धाम में पर्यटन सहित उद्योग धंधे स्थापित करने के भी प्रयास किये जाएंगे। जो लोग उद्योग स्थापित करेंगे उन्हें सुविधाएं भी मुहैया कराई जायेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गरीब के घर में भी गैस चूल्हा होने के सपने को

साकार किया है। उन्होंने बताया कि संत शिरोमणि पंडित रवि शंकर जी महाराज रावतपुरा सरकार सामाजिक समरसता की मिसाल है। उनके द्वारा समाज सेवा और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से की जाने वाली राष्ट्र की सेवा अनुकरणीय है। उन्होंने मानवता की सेवा के लिए छिपरी धाम बनाया है, छिपरी को मातृ धाम का नाम देने के पीछे जो उद्देश्य है, वह मां की महिमा पर आधारित है। भारत देश में जो संस्कार हमें मिले हैं, उसमें मां को सर्वोपरि माना गया है। उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि पंडित रवि शंकर जी महाराज का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, यही हमारी कामना है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना की तरह ही मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जितनी राशि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के खाते में साल भर में डालती है, उतनी ही राशि मध्यप्रदेश सरकार भी किसानों के हित में उनके बैंक खाते में डालती है। जिस प्रकार सेना का जवान देश की सेवा कर रहा है, वैसे ही किसान भी सभी का पेट भरता है। डॉ. यादव ने कहा कि हमारी एक-एक सांस हमें प्रतिदिन मौत और जीवन से साक्षात्कार कराती है। यदि हम अपने शरीर की शारीरिक रचना समझ लें तो हमें पूरा ब्रह्मांड भी समझ में आ जायेगा। केन्द्रीय मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने कहा कि रावतपुरा सरकार के कारण टीकमगढ़ की पावन धरती छिपरी धाम धन्य हुई है। उन्होंने कहा कि रावतपुरा सरकार पर्यावरण संरक्षण सहित समाज सेवा के क्षेत्र में अनेक कार्य कर रहे हैं। इसी के तहत 2 लाख पौधे रोपित करने का कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। सांसद श्री वी.डी. शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आज महिलाओं, किसानों और गरीबों के कल्याण की चार योजनाओं के तहत राशि अंतरित करने का पुण्य कार्य किया है। इसके लिये उन्होंने डॉ. यादव का साधुवाद किया।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008